

>

Title: Need to fix criteria for identifying the people living below poverty line in the country.

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): माननीय सभापति महोदय, गरीबी रेखा का मानक निर्धारण एवं गणना के संबंध में सरकार का ध्यान अविश्वसनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2011 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 443 के उत्तर में सरकार के योजना आयोग मंत्रालय द्वारा यह कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का मानक 965 रूपए प्रति माह प्रति व्यक्ति है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 781 रूपए प्रति माह प्रति व्यक्ति निर्धारित है। इससे अधिक कमाने वाला गरीब परिवार का व्यक्ति अमीरी रेखा में आएगा। प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा गया कि गरीबी रेखा का निर्धारण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है तथा विशेषज्ञ अपने-अपने ढंग से इसकी अलग-अलग व्याख्या कर सकते हैं।

उपरोक्त बातों से सिद्ध हो रहा है कि सरकार गरीबी रेखा के निर्धारण में रुचि नहीं ले रही है। आज़ादी के बाद अभी तक सरकार गरीबी रेखा का पैमाना निर्धारित नहीं कर सकी है। भारत जैसे विशाल देश में जहां जनता के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण ही नहीं हो सकता है, वहां गरीबी दूर करने हेतु योजनाएं किस आधार पर बनायीं जा रही हैं? गरीब भगवान के सहारे जी रहा है। सरकार ने स्वयं मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है कि गरीबी रेखा के निर्धारण की एक जटिल प्रक्रिया है।

क्या गरीबी रेखा के निर्धारण की इस जटिल प्रक्रिया का कोई हल निकलेगा? क्या वर्ष 2012 में नए तरीके से गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु सरकार कोई योजना बना रही है? यदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार विनिहृत नहीं कर सकी है तो उन परिवारों को सहायता किस आधार पर दी जा रही है? क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का राज्यवार ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध है? यदि नहीं, तो सरकार किस आधार पर गरीबों को सहायता दे रही है?

अतः आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस अविश्वसनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा कराई जाए एवं सरकार उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना वक्तव्य जारी करे।